*वृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन**

शक्तिकान्त दास

मैं सबसे पहले बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बेशक यह संबोधन आभासी माध्यम पर होगा क्योंकि यही मौजूदा समय की बाध्यकारी वास्तविकता है। मैं बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 184 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। देश के सबसे पुराने सेवारत चैंबर होने के साथ-साथ, आपने इस शहर ही नहीं बल्कि राष्ट्र की नियति पर भी अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 'कॉर्पोरेट ऐज़ ए सिटीजन' के तत्त्वावधान में, कारोबार में नैतिक व्यवहार, कौशल प्रशिक्षण एवं संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए, यह चैंबर वृहत्तर और अधिक न्यायसंगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आप अपने प्रयासों में पूर्णतः सफल हों, इसके लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस महामारी से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए चैंबर हर संभव कोशिश कर रहा है। वस्तुतः, आज के अपने संबोधन को मैं 'वृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन' विषय पर केंद्रित करना चाहूँगा।

यद्यपि महामारियाँ विरल घटनाएँ होती हैं और वे शायद ही अपने पिछले अध्यायों कों दुहराती हों, फिर भी उनके प्रभावों और नीतिगत उपायों का अध्ययन से हमें बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। भारत में ऐसी चार भयंकर महामारियों, यथा 1896 के प्लेग, 1918 के स्पैनिश फ्लू, 1958 के एशियन फ्लू और 1974 के चेचक ने दर्शाया है कि इन सभी महामारियों के दौरान जीडीपी में संकुचन/मंदी आई है। और, जान-माल की क्षति के हिसाब से, 1918 का स्पैनिश फ्लू 'मदर ऑफ ऑल पैनडेमिक्स' यानी महामारियों की जननी रहा । हालांकि यह देखा गया है कि हालात में बहुत तेज़ी से सुधार आया और महामारी के दो वर्षों के अंदर ही हालात सुधर गए। केवल स्पैनिश फ्लू की महामारी इसका अपवाद रही जिसमें चार वर्ष बाद 1922 में जीडीपी प्रति व्यक्ति, महामारी-पूर्व स्तर पर दुबारा पहुँच पाई। इन महामारियों के बाद नीतिगत उपायों में चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान करने और इसके साथ ही, अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभावों को कम करने पर अनिवार्य रूप से ध्यानकेंद्रित किया गया। यह देखा गया कि वृद्धि, सरकारी व्यय पर अत्यधिक निर्भर हो गई, जबकि अपवादस्वरूप किए गए राजकोषीय उपायों से समय पर और सुचिन्तित तरीके से बाहर निकलना निकट भविष्य में समष्टि-आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए, निजी उपभोग पर व्यय एवं निवेश को तेज करने पर नीतिगत ध्यान देना ही सबसे जरूरी था।

कोविड-19 महामारी के दौरान राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय

पिछला वर्ष पूरे विश्व में अकल्पनीय कष्टों और दुखों का साक्षी रहा है और इसमें जान-माल की बहुत ही भयंकर क्षति हुई है। पूरे विश्व की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने इसके विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए सभी परंपरागत और अपरंपरागत नीतिगत उपाय किए। वैश्विक स्तर पर, सरकारों ने महामारी की रोकथाम के लिए 2020 में बड़े-बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज दिये, जो करीब 14 ट्रिलियन डॉलर (वैश्विक जीडीपी का 13.5 प्रतिशत) था (आईएमएफ़, 2021)। इसके परिणामस्वरूप, घाटा और कर्ज के स्तरों में उछाल आ गया। भारत में भी, केंद्रीय सरकार ने आर्थिक पैकेजों की एक श्रृंखला घोषित की, जिसमें सबसे पहले समाज के कमजोर तबकों को बचाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके बाद, वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए उपभोग और निवेश को गति प्रदान करने के लिए प्रति-चक्रीय उपाय किए गए।

दूसरी तरफ, केंद्रीय बैंकों ने, अग्रसक्रिय होकर कई परंपरागत और अपरंपरागत मौद्रिक नीति संबंधी उपायों की रूपरेखा बनायी और उन्हें कार्यान्वित किया, जो उनके अनुभवों और पिछले संकटों, और खासकर 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफ़सी) पर आधारित थे। अधिकतर केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरें घटा दी हैं, पात्र प्रतिपक्षकारों के दायरे को बढ़ा दिया है और संपार्श्विक नियमों को आसान बना दिया है, वहीं रेपो परिचालनों की मात्रा और अवधि को भी बढ़ा दिया है। उन्होंने, महामारी-जनित उच्च अनिश्चितता को कम करने और निम्नतर दीर्घावधि ब्याज दरों की

* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गुरुवार, 25 फरवरी 2021 को दिया गया संबोधन।

सुविधा देने के लिए, अपने आस्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) भी विस्तारित कर दिये हैं। इन उपायों को, भविष्य की मौद्रिक नीति के 'रुख' को संप्रेषित करते हुए, अंतर्निहित और सुस्पष्ट भावी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) से और अधिक सशक्त बनाया गया।

भारत में, रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 के मद्देनजर कई परंपरागत और अपरंपरागत उपाय किए। अपरंपरागत उपायों के अलावा, आरबीआई ने दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की शुरुआत की ताकि सिस्टम और क्षेत्र-विशेष चलनिधि को बेहतर बनाया जा सके और क्षेत्रवार ऋण अवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा दबाव को दूर किया जा सके। कतिपय अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफ़आई) को विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं, वहीं मोचन दबावों को कम करने के लिए म्यूचुअल फ़ंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़-एमएफ़) की भी शुरुआत की गयी। कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, आरबीआई की आस्ति खरीद से इसके तुलन पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए, इसने केंद्रीय बैंकिंग के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। ये खरीद जोखिम-मुक्त सरकारी (सॉवरिन) बॉन्डों (राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों सहित) तक सीमित थीं। वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने पर ही हमारा ध्यान केंद्रित था। साथ ही, सहकारी परिणाम हासिल करने के लिए, भावी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) को रिज़र्व बैंक की संचार रणनीति में प्रमुखता दी गई। हालत में सुधार को बल देने के लिए प्रचुर चलनिधि सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता ने चलनिधि संबंधी भय को दूर कर दिया और बाजार के मनोभावों को बल प्रदान किया। हम वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए, प्रचुर चलनिधि के प्रावधान के जरिये हालात में सुधार की प्रक्रिया को समर्थन देना जारी रखेंगे।

व्यापार और भुगतान संतुलन पर प्रभाव

जीडीपी और व्यापार में कोविड-19 जनित गिरावट के प्रभाव की तुलना यदि 2008 के जीएफ़सी से की जाए तो विपरीत प्रवृतियों का पता चलता है। 2020 के दौरान वैश्विक जीडीपी में अनुमानतः 3.5 प्रतिशत का संकुचन हुआ है, जो जीएफ़सी के दौरान हुए 0.1 प्रतिशत की तुलना में बहुत ज्यादा है। वहीं 2020 के दौरान वाणिज्यिक व्यापार में 9.2 प्रतिशत संकुचन हुआ है जबकि 2009 में यह 22.3 प्रतिशत था। इस भिन्नतायुक्त पैटर्न के पीछे, हाल के घटनाक्रम के दौरान विभिन्न देशों में लॉकडाउन से प्रेरित विभिन्न घरेलू कारकों की ही प्रमुख भूमिका रही होगी।

यद्यपि वाणिज्यिक व्यापार में 2020 के अंत से पुनरुद्धार के प्रारम्भिक संकेत मिलने लगे हैं, सेवा क्षेत्र में हालात में सुधार अभी भी गति नहीं पकड़ पाया है क्योंकि सुस्त सीमापार पर्यटन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण इस क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन पर अब भी असर पड़ रहा है। कुछेक एशियाई देशों और चिकित्सा उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे कतिपय क्षेत्रों द्वारा असमान वैश्विक व्यापार के हालात में सुधार हुआ लेकिन यह कब तक बरकरार रहेगा यह एक चिंता का विषय है। वैश्विक व्यापार गतिविधियों के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण बाधा है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अब भी जारी व्यवधान। नवंबर 2020 से लदान लागतों में बहुत तेज वृद्धि हुई है और माल सुपुर्दगी समय भी खिंच गया है, जिससे समान की कीमतों में तेजी आई है। इन मुद्दों पर समूचे विश्व के नीति निर्माताओं द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना अपरिहार्य है।

मांग और आपूर्ति आघातों का प्रभाव भुगतान संतुलन पर भी परिलक्षित होता है। एक ओर, पण्य-निर्यातक देशों ने, अपने व्यापार के निवल मान पर ऋणात्मक आघातों के कारण, चालू खाते में निम्नतर अधिशेषों का सामना किया, वहीं दूसरी ओर, भारत जैसे निवल पण्य-आयातक देश इससे लाभान्वित हुए और कम घाटा दर्ज किया। यहाँ तक कि अधिशेष भी दर्ज किया। कच्चे तेल की कीमतें कम होने और महामारी के आरंभिक दिनों में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के कारण कमजोर मांग होने की वजह से अप्रैल-जनवरी 2020-21 के दौरान भारत के तेल आयात बिल में 42.5 प्रतिशत की कमी आयी। वस्तुओं के व्यापार के विपरीत, यात्रा प्रतिबंधों के कारण यात्रा से होने वाली आय में तेजी से हुई गिरावट के बावजूद भारत के सेवाक्षेत्र का निवल निर्यात अपेक्षाकृत सुदृढ़ रहा। अधिकांश अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत के सेवाक्षेत्र के निर्यात को सॉफ्टवेयर निर्यात से बल मिला। घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों को कोर ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं के लिए वैश्विक मांग बढ़ने से लाभ मिला क्योंकि महामारी के दौरान उनके ग्राहकों का फोकस आईटी संचालन के लिए नए मॉडल पर केंद्रित रहा। मेजबान देशों में बड़े पैमाने पर नौकरियां समाप्त होने के कारण विप्रेषण के अंतर्वाहों में कमी आई। इसके बावजूद व्यापार घाटा कम होने और सेवाओं का निवल निर्यात मजबूत होने की बदौलत विप्रेषण में आयी गिरावट की अच्छी खासी भरपाई हुई।

जैसा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने उल्लेख किया है, भारत के आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) का रुख़ वैश्विक प्रवृति के विपरीत रहा और डिजिटल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने के कारण इसमें वर्ष 2020 में सकारात्मक रूप से वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में, भारत में 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ जो एक साल पहले के 31.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। भारत के आशावादी विकास दृष्टिकोण और पर्याप्त वैश्विक चलनिधि की स्थिति ने भी वर्ष 2020-21(19 फरवरी तक) में घरेलू इक्विटी बाजार में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रेरित किया। अनिवासी भारतीयों ने भी भारत में बैंकों में राशि जमा करने में बहुत बढ़ोतरी की। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान चालू और पूंजी खाता दोनों में अधिशेष की स्थिति रही जो विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। 19 फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 583.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2020 समाप्त होने के बाद से 106.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। घरेलू और वैश्विक सुधार दोनों से जुड़ी प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों द्वारा बाह्य क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव जारी रहेगा।

कोविड के बाद भारत में उभरते अवसर

अब मैं भारत में कोविड के बाद कुछ उभरते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने विशेष रूप से उल्लेखनीय सात प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है।

(i) विनिर्माण और आधार-संरचना

विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि में सुधार हेतु अग्रणी भूमिका निभा रहा है जबकि सघन रूप से एक-दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित कई सेवाओं के उप-क्षेत्रों को इस संकट ने बुरी तरह प्रभावित किया है। एक सशक्त विनिर्माण क्षेत्र और आधार-संरचना को विकसित करने की दिशा में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान और केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत की गई पहल से बाकी क्षेत्रों के साथ इसके मजबूत जुड़ाव को स्वीकार किया गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना है। यह श्रम बाजार में सुधारों के साथ-साथ, विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक उन्नत वक्र रेखा में विकास को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो सकता है और इसकी रोजगार क्षमता का लाभ उठा सकता है।

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मौजूदा सदस्यता का लगभग दो-तिहाई हिस्सा छोटे और मझोले उद्यमों का है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र लगभग 6.33 करोड़ उद्यमों के विशाल नेटवर्क के साथ अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में उभरा है, जिसका योगदान हमारे सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 48 प्रतिशत[1] का है। यह क्षेत्र लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और इस मामले में केवल कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। यह क्षेत्र महामारी के दौरान विशेष रूप से कमजोर हुआ है, जिसके कारण दबाव से निपटने और इस क्षेत्र के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इस संबंध में, सरकार द्वारा दो प्रमुख योजनाएं, अर्थात, आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और गौण ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती, उच्च संरचनात्मक और टिकाऊ चलनिधि, ऋण चुकौती पर स्थगन, परिसंपत्ति वर्गीकरण पर रोक, ऋण पुनर्गठन पैकेज और नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को संवितरित ऋण पर सीआरआर छूट के रूप में विभिन्न प्रकार के मौद्रिक और विनियामक उपायों द्वारा इनको विधिवत सहयोग प्रदान किया गया है। इन उपायों से न केवल एमएसएमई क्षेत्र में तनाव को कम करने में सहायता मिलेगी बल्कि नए अवसर भी खुलेंगे। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक एमएसएमई क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को सहयोग देने के लिए तैयार है।

(iii) प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष

भारत में डिजिटल विस्तार ने एक नई ऊँचाई हासिल कर ली है। अब समय आ गया है कि इसके अनुप्रयोगों का लाभ उठाया जाए और साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। लगभग 1.2 बिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर और 750 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर के साथ, भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है[2]।

---

[1] एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

[2] 31 मार्च, 2020 के अनुसार। स्रोत: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)।

डिजिटल क्षमताओं में सुधार और संयोजकता के सर्वव्यापी होने के साथ ही तकनीकी नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी संचालित क्रांति भारत की अर्थव्यवस्था को जल्दी ही और मौलिक रूप से बदलने के लिए तैयार है। उनके पास कृषि, विनिर्माण और व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच में सुधार करने की क्षमता है। इसके कारण वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बेहतर होने की संभावना है और सूचना की असमानता और ऋण जोखिम कम हो सकता है। इसी तरह, खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑडियो-विज़ुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा द्वारा आवश्यक कौशल और स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले कौशल के बीच तालमेल को सुदृढ़ किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन, स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से निदान और डॉक्टर के दूरस्थ प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है । कृषि उत्पादों की बिक्री का मार्गदर्शन करने के लिए वास्तविक समय बाजार की जानकारी का उपयोग करके और कृषि निर्गमों के मार्गदर्शन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मृदा, जल और जलवायु आंकड़ों का उपयोग करके 'सटीक खेती' हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अंगीकरण कृषि क्षेत्र में उच्च मूल्य वर्धन कर सकता है । लेन-देन की अपनी कम लागत के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र पहले से ही बाजार संरचना में क्रांति ला रहा है जिसकी पराकाष्ठा गहन बाजार एकीकरण में हुई है ।

मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत में अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय (जीईआरडी) मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रेरित है जिसमें कुल अनुसंधान एवं विकास में 56 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एक वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार अधिनायक बनने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र आगे आए जैसा कि कई उभरते बाजारों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हुआ है ।

(iv) स्वास्थ्य

कोविड-19 के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र निस्संदेह एक प्रमुख कमजोरी (फॉल्ट लाइन) के रूप में और साथ ही जबरदस्त विकास अवसरों के क्षेत्र के रूप में उभरा है । 3000 से अधिक कंपनियों के नेटवर्क के साथ, भारत अब संख्या के अनुसार फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, इस क्षेत्र में सालाना 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार अधिशेष पैदा हो रहा है। भारत अब टीकों की वैश्विक मांग के आधे से अधिक की आपूर्ति करता है । इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और कम उत्पादन लागत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि दिखाई पड़ने की उम्मीद है । कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में यह आशा की जाती है कि टीकों और दवाओं के लिए बढ़ी हुई वैश्विक मांग की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी। भविष्य में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए किफ़ायती रूप से मूल्य श्रृंखला के हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र आपूर्ति बढ़ाई जाए। कॉरपोरेट सेक्टर को इस क्षेत्र में स्तर और कौशल सृजन के लिए ज्यादा निवेश करने की जरूरत है।

(v) निर्यात को प्रोत्साहन

वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे अपनी गहरी मंदी से उबर रही है, वैश्विक व्यापार गतिविधि के आगे चक्रीय उत्थान की स्थिति में होने की संभावना है। भारत के मामले में, ऐसे संरचनात्मक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जो मजबूत विकास और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में घरेलू उद्योग की व्यापक भूमिका की नींव रख सकते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों और संभावित अवसरों पर आधारित पीएलआई योजना कुछ ऐसे विजेता क्षेत्रों की पहचान करती है जो घरेलू निर्माताओं को किफायत प्राप्त करने में और वैश्विक बाजार में उनके पदचिह्नों का विस्तार करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस योजना के बारे में कंपनियों से प्राप्त प्रतिक्रिया- विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण उद्योग में बहुत उत्साहजनक बतायी गयी है। यह निर्यात प्रोत्साहन खाद्य उत्पादों अन्य क्षेत्रों जैसे परिधान और वस्त्र; पूंजीगत वस्तुएं; ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर्स से भी आने की संभावना है; चूंकि पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन संरचना की परिकल्पना अगले पांच वर्षों के लिए की गई है, इसलिए घरेलू उद्योग को दीर्घावधि में व्यवहार्य बने रहने के लिए गुणवत्ता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके अपनी ताकत विकसित करने की जरूरत है ।

(vi) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

एक अन्य नीतिगत क्षेत्र, जिसकी भारत के निर्यात और विकास को टिकाऊ प्रोत्साहन देने के लिए ध्यान देने की जरूरत है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। संभावित एफटीए को न केवल

घरेलू ताकत और वैश्विक अवसर बल्कि महामारी के बाद की अवधि में उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य को भी संज्ञान में लेने की जरूरत है। भावी एफटीए को तैयार करते समय, एफटीए के साथ भारत का अनुभव एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक हो सकता है। प्रमुख विचार उन देशों और क्षेत्रों की पहचान करने में होना चाहिए जिनमें न केवल घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक बाजार के रूप में संभावना है बल्कि उनमें घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाने की गुंजाइश है, विशेष रूप से पीएलआई योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों में। ब्रेक्सिट के बाद का परिदृश्य ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ अलग व्यापार समझौतों के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करता है। एफटीए इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ न केवल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा दे सकता है बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में भी अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है । अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण, अफ्रीका में भारतीय फर्मों से निर्यात और निवेश की अपार संभावनाएं भी पैदा हो गई हैं। भारतवशियों की बड़ी उपस्थिति इस क्षमता का दोहन करने में मदद कर सकती है।

(vii) सेवा निर्यात

विश्व सेवा व्यापार में सुधार, जो महामारी के पूर्व की अवधि में माल व्यापार की तुलना में तेजी से हुआ के वर्तमान सीमा पार यात्रा प्रतिबंधों के कारण धीमी रहने की उम्मीद है। तथापि दक्षता के साथ व्यापार किए जाने पर अधिक जोर दिया रहा है। इसमें अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग बढ़ी है और लाए गए निरंतर वैश्विक मूल्य शृंखला पुनर्संरचना (ग्लोबल वैल्यू चेन रीकॉन्फिगरेशन) द्वारा नए व्यवसाय के अवसर बढ़े हैं। इससे आईटी कंपनियों के सॉफ्टवेयर निर्यात में सुदृढ़ता भी आई है। डब्ल्यूटीओ (फरवरी 2021) के एक हालिया अध्ययन में आकलन है कि 2030 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण वैश्विक व्यापार में वृद्धि औसतन 2 प्रतिशत सालाना अधिक होगी। इससे व्यापार लागत को कम करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने से व्यापार के लिए नए अवसर खुलेंगे। डिजिटलीकरण पर हमारे द्वारा अधिक ध्यान दिए जाने को देखते हुए, भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक देश होने के नाते, बढ़ी हुई सेवाओं का हमें लाभ मिलने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, हम एक निर्णायक परिवर्तन की संक्रांति पर हैं। सारी दुनिया के विपरीत, भारत में कोविड-19 के मामलों में गिरावट आई है और हमारे लिए इस गिरावट का लाभ उठाना और कड़ी मेहनत से अर्जित सफलता को आधार बनाकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण के मामले फिर से शुरू हो गए हैं। हमें सतर्क, दृढ़ और तैयार रहने की जरूरत है। कोविड युद्ध जारी है। 2020 की लड़ाई जीती गई है लेकिन इसके लिए जीवन, आजीविका और आर्थिक गतिविधियों के मामले में काफी अधिक कीमत चुकानी पड़ी है। हमें 2021 की लड़ाई भी जीतने की ज़रूरत है। आइए, इस युद्ध को भी अंतत: जीत लेने का संकल्प लें।

धन्यवाद, सुरक्षित रहें, नमस्कार।